



समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा

विशेष समाचार

तेरे कूचे से बेआबरू होकर निकले... >> पेज 02

डॉ. अखिलेश दास गुप्ता की 9वीं ... >>पेज 04

92 की उम्र में सुरों की मलिका का...

फास्ट न्यूज

अलविदा आशा भोसले, कभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो से निकाला गया

मुंबई। सुरों की मलिका आशा भोसले का आज 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें शनिवार रात चेस्ट इन्फेक्शन के चलते मुंबई के बीच कैदी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। उन्होंने कई भाषाओं में रिकॉर्ड 12 हजार गाने गाए। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब आशा को यह कहकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो से निकाल दिया गया कि उनकी आवाज खराब है। >>विस्तृत समाचार (पेज 3)

सरकार जाति जनगणना को ठंडे बस्ते में डालना चाहती : जयराम रमेश

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार जाति जनगणना को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। साथ ही महिला आरक्षण कानून में बदलाव के जरिए देश को गुमराह कर रहा है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा- सरकार अनुच्छेद 334-A में संशोधन की बात कर रही है। यह तर्क दे रही है कि जाति जनगणना के नतीजे आने में समय लगेगा। लेकिन बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों ने 6 महीने से कम समय में जाति सर्वे पूरा किया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार का छिपा हुई एजेंडा है। सरकार का असल मकसद जाति जनगणना नहीं कराना है। अनुच्छेद 334-A में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने को जनगणना और परिसीमन से जोड़ा गया है।

100 की स्पीड में बस ने पिकअप को उड़ाया, 13 मौतें कटिहार। बिहार के कटिहार में शनिवार देर शाम बस और पिकअप की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक ही परिवार के 5 लोग शामिल हैं। मुक्तकों में 10 महिलाएं, 2 पुरुष और एक बच्ची है। इसमें 11 मृतक पूर्णिया जिले के रहने वाले थे, जबकि दो कटिहार के हैं। हादसे में 32 से ज्यादा घायल हैं। इनमें 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा कटिहार के कोढ़ा ब्लॉक में NH-31 पर हुआ। बस से टक्कर के बाद लोगों के शव सड़क पर बिखर गए।

ईरानी नौसेना ने अमेरिकी जहाज को होर्मुज पार करने से रोका



ट्रम्प बोले- ईरान को टोल दिया तो रास्ता नहीं मिलेगा, ईरान बोला- टोल देना ही पड़ेगा

डोनाल्ड ट्रम्प ने जहाजों की नाकाबंदी का किया ऐलान

ऐलान

तमसा संकेत, एजेंसी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐलान किया है कि अमेरिकी नेवी अब होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की नाकाबंदी करेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि जो भी जहाज इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा, उसे रोका जाएगा और जांच की जाएगी। खास तौर पर उन जहाजों पर नजर रखी जाएगी, जिन्होंने ईरान को टोल दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच कल पाकिस्तान में 21 घंटे चली शांति वार्ता बेनतीजा रही। रिपोटर्स के मुताबिक दोनों के बीच होर्मुज स्ट्रेट खोलने और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पंच फंसा है। ट्रम्प ने कहा है कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। इससे दुनिया के कई देशों और लोगों में डर और परेशानी बढ़ी है। ट्रम्प ने कहा कि ईरान ने समुद्र में बारूदी सुरंगें होने की बात कही है, जिससे जहाजों के लिए खतरा पैदा हो गया है। इसी वजह से कोई भी जहाज इस रास्ते से



ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के साथ हुए युद्ध में अब तक 3,375 लोगों की मौत हो चुकी है। यह जानकारी ईरान की फॉरेंसिक मेडिसिन संस्था के प्रमुख अब्बास मस्जेदी अरानी ने दी है। उन्होंने बताया कि मरने वालों में 2,875 पुरुष और 496 महिलाएं शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, यह आंकड़ा उन शवों की पहचान के बाद सामने आया है, जिनकी जांच फॉरेंसिक टीमों ने की। कई मामलों में शवों की पहचान करना मुश्किल था, क्योंकि हमले काफी बड़े पैमाने पर हुए थे।

जाने में जोखिम नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा कि इससे ईरान की इमेज को नुकसान पहुंचा है और अब उसे जल्दी से यह रास्ता खोलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐलान किया है कि अमेरिकी नौसेना जल्द ही होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजही पर नाकाबंदी शुरू करेगी। जो भी जहाज

पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स

- **पाकिस्तान में बातचीत बेनतीजा:** अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की इस्लामाबाद में ईरान के साथ बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। वेंस ने कहा कि हमें पूरी तरह भरोसा चाहिए कि ईरान न तो परमाणु हथियार बनाएगा और न ही ऐसी तैयारी करेगा जिससे वह जल्दी हथियार बना सके।
- **अमेरिका ने माइंस हटाने का अभियान शुरू किया:** अमेरिकी सेना के सेंटकॉम (CENTCOM) ने कहा है कि अमेरिकी युद्धपोत समुद्री रास्ते को सुरक्षित बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आरोप है कि ईरान ने इस अहम समुद्री मार्ग में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं।
- **नेतन्याहू बोले- अभियान अभी खत्म नहीं:** इजराइल के प्रधानमंत्री बेनजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। उनका कहना है कि हमले इसलिए किए गए क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब था। उन्होंने दावा किया कि इन हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा नुकसान पहुंचा है।
- **इमोशानल मैसेज:** ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाशु शक्रवार रात प्लेन में बच्चों की तस्वीरें रखकर पाकिस्तान पहुंचे। ये बच्चे 28 फरवरी को मिसाइल हमले में मारे गए थे। इसका इल्जाम अमेरिका-इजराइल पर लगा था।
- **लेबनान में हमले जारी:** लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, तुफानहा इलाके में हुए हमलों में 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर है।

इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा, उसे रोका जाएगा। उन्होंने ईरान पर आरोप लगाया कि वह इस रास्ते के जरिए दुनिया से जबर्न पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा है। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका इस तरह के दबाव को कभी नहीं मानेगा। >> (शेष पेज 04 पर)

>> डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम

सूर्योदय: 05:45

सूर्यास्त: 06:29

अधिकतम: 36°00

न्यूनतम: 26°00



अब 15 साल का हिसाब देना होगा, सिलीगुड़ी की जनसभा उनकी नींद उड़ा देगी

टीएमसी ने मदरसों के लिए 6000 करोड़ दिए : मोदी

जनसभा

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि TMC ने मदरसों के लिए 6000 करोड़ दिए, लेकिन विकास के लिए कुछ नहीं किया। वह सिर्फ अपने खास वोट बैंक के लिए पैसे देती है। आपने TMC के शासन काल में बंगाल की बर्बादी देखी है। अब उन्हें 15 साल का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल से TMC का जाना तय है। कल



मेरे रोड शो में लोगों ने जो प्यार दिखाया, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आज सिलीगुड़ी की यह जनसभा TMC की नींद उड़ा देगी। PM का आज पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। उन्होंने सिलीगुड़ी में जनसभा की। >> (शेष पेज 04 पर)

पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अय्यूब ने सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया स्वागत

तमसा संकेत, संवाददाता



संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने की बात कही। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सम्मेलन के दौरान नेताओं ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अधिक से अधिक लोगों तक पार्टी की

नीतियों और विचारों को पहुंचाएं। साथ ही संगठन को मजबूत बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। पूरे कार्यक्रम के दौरान अनुशासन और सौहार्द का माहौल बना रहा। कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह साफ नजर आया। सम्मेलन का समापन शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, जहां नेताओं ने भविष्य की रणनीति और संगठन विस्तार को लेकर संकेत दिए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. अय्यूब ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान नीतियों का असर आम लोगों पर पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि यदि उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो कई फैसलों में बदलाव किया जाएगा।

घोषणा : 28 अगस्त को खत्म होगी, 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे

अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से, 57 दिन चलेगी

तमसा संकेत, एजेंसी

यात्रा में इस बार क्या-क्या नया ...

- मनोज सिन्हा के मुताबिक पिछले सालों की तुलना में व्यवस्थाओं में 25% की वृद्धि की गई है। ट्रैकिंग और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए RFID कार्ड की शुरुआत की गई है।
- तीर्थयात्रियों के लिए ग्रुप एक्सीडेंटल इश्योरेंस कवर को दोगुना करके 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया है।
- यात्रा के दौरान इस्तेमाल होने वाले टटुओं (पोनीज) की मौत होने पर 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा।

किमी लंबा नुनवान-पहलगाम रूट और गांदरबल से 14 किमी लंबा बालटाल रूट खुला रहेगा। LG सिन्हा ने बताया कि देशभर में लगभग 556 तय बैंक शाखाओं के जरिए यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, जबकि श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यस बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक की ब्रांचेस में यात्रा के रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध रहेंगे। >> (शेष पेज 04 पर)



लाल जी टंडन कृत पुस्तक स्मृति नाद का लोकार्पण

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने किया संबोधित

- जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरि और राजनाथ सिंह ने दीप जलाकर लालजी टंडन की पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
- राजनाथ सिंह ने लखनऊ महानगर पूर्व महामंत्री राम अख्तर कनौजिया की पत्नी रानी कनौजिया के चित्र पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की।



राज्यपाल लालजी टंडन की पुस्तक 'स्मृति नाद' का विमोचन किया। कार्यक्रम की शुरुआत जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरि की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके पहले राजनाथ सिंह ने वरिष्ठ नागरिकों से सीधा संवाद किया। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मंडलों से 5 ए

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पूर्व

>> (शेष पेज 04 पर)

प.बंगाल में एसआईआर : सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

वोटरलिस्ट से 91 लाख नाम कटे थे, 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग

सुनवाई

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट सोमवार को SIR पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्ल्या बागची की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह मतदाता सूची फ्रीज होने के खिलाफ नई याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करेगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट मालदा जिले में SIR प्रक्रिया के दौरान सात न्यायिक अधिकारियों के घेराव से जुड़े मामले में भी सुनवाई करेगा। >> (शेष पेज 04 पर)



बंगाल में 11.85% नाम हटे

पश्चिम बंगाल में अक्टूबर 2025 में कुल वोटर 7.66 करोड़ थे। इनमें से अब तक 90.83 लाख नाम हटाए गए। लगभग 11.85% वोटर कम हो गए। यानी अब राज्य में 6.76 करोड़ वोटर हैं। चुनाव जिले में फाइनल आंकड़े जारी नहीं किए हैं। इसके अलावा जांच के तहत आए 60.06 लाख वोटर्स में से 27.16 लाख के नाम हटाए गए।

सम्पादकीय

ज्ञानेश कुमार को गुस्सा क्यों आता है?



चुनाव आयोग की तुलना कांग्रेस को दो टुक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भयरहित, हिसारहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छाप्रा रहित, बूथ और सोर्स जॉर्मिंग रहित होकर ही रहेगे। पहले तो यह संदेह हुआ कि यह वाकई चुनाव आयोग ने लिखा है या किसी ने आयोग की छवि खराब करने के लिए इस तरह तुणमूल कांग्रेस का नाम लेकर दो टुक बात कही है। क्योंकि पहले चुनाव से लेकर अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब चुनाव आयोग ने सीधे किसी दल का नाम लेकर उसके लिए इस भाषा में बयान दिया हो। विपक्ष और आयोग के बीच कई बार रस्साकशी हुई है। बीते कुछ सालों में यह तनाव ज्यादा बढ़ गया है। जिसमें विपक्ष बार-बार चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाता है और इस बार तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव लाने की तैयारी भी विपक्ष ने कर ली थी, जो सफल नहीं हुई। लेकिन इन सबके बावजूद चुनाव आयोग में बैठे लोगों ने किसी एक दल का नाम लेकर ऐसी टिप्पणी नहीं की, जो अब की गई है। इसके बाद अब यही बचता है कि चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं का नाम लेकर उन्हें जवाब देने लगे। क्योंकि निष्पक्षता नाम की खिड़िया शायद डाल से उड़ चुकी है। यह पोस्ट चुनाव आयोग ने ही डाली है, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है, क्योंकि इसकी बाकायदा पृष्ठभूमि भी सामने आई है। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद 90.66 लाख वोटर्स के नाम हटाने के विरोध में टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिला। 'डेरेंक ओ ब्रायन, सागरिका घोष, साकेत गोखले और मेनका गुरुस्वामी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। टीएमसी के इस दल ने मुख्यतः दो बातों पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा कि ममता बनर्जी ने अब तक नौ पत्र चुनाव आयोग को लिखे हैं, लेकिन लंबे समय से आयोग चुप बैठा है, पत्रों का जवाब नहीं दे रहा। और दूसरी शिकायत नंदीमार में मुख्य चुनाव अधिकारी और एक वरिष्ठ भाजपा नेता के बीच कथित सांठगांठ को लेकर थी। ये कोई ऐसी शिकायत नहीं है, जिनका जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन चार लोगों के साथ यह बैठक केवल सात मिनट ही चली। टीएमसी का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनकी बातें नहीं सुनी और सात मिनट की बातचीत के बाद उन्हें गेट आउट कहा। डेरेंक ओब्रायन ने कहा, 'चुनाव आयोग ने हमें अपमानित किया और परिसर छोड़ने को कहा। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी फैलाई। यह भाजपा की साजिश है। लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है।' आपको बता दें कि चुनाव आयोग की उपरोक्त पोस्ट इस बैठक के बाद ही आई है। आयोग इस बात पर इटला रहा है कि उसने टीएमसी को दो टुक जवाब दे दिया, लेकिन क्या यह शर्मिन्दगी की बात नहीं होनी चाहिए कि एक राजनीतिक दल के सवालों का सतोषजनक जवाब देने की जगह यह खिड़िया पीटा जाए कि हमने दो टुक जवाब दे दिया। इसका एक अर्थ यह भी होता है कि चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानता है। राजनीति बुधवार की बैठक के बारे में टीएमसी के आरोपों पर निर्वाचन आयोग का कहना है कि टीएमसी सांसद डेरेंक ओ ब्रायन ने मीडिया ने लिखतों हुए कहा कि हम यहां बात सुनने नहीं आए हैं। इसके बाद मीडिया में माहौल गरमा गया और टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल चला गया। हालांकि अब इस दल के सदस्यों ने निर्वाचन आयोग को चुनौती दी है कि वह इस बैठक की ट्रांसक्रिप्ट जारी करे। टीएमसी ने यह भी कहा है कि अगर आयोग इसे जारी नहीं करेगा तो हम इसे जारी करेंगे। अब बैठक किस वजह से पूरी नहीं हुई और किसने पहले आधा खाना, क्यों खोया? और क्या ऐसी तानाबनी लोकतंत्र के लिए सही है? इन सारे सवालों के जवाब देश को दिए जाने चाहिए, इसकी पहल चुनाव आयोग से ही होना चाहिए। क्योंकि ऊंगलियां उसी पर उठी हैं। वैसे बैठक में बहस का एक और वाक्या प.बंगाल के संदर्भ में भी पेश आया। जहां बुधवार को ही ज्ञानेश कुमार वरुणमंड मीडिया ले रहे थे और सभी अधिकारियों से बारी-बारी से पूछ रहे थे कि उनके यहां कितने पेलिंग बूथ आदि हैं। जब यूरी कैडर के सदस्यों ने निर्वाचन आयोग को चुनौती दी है कि वह इस बैठक पर अनुगम यादव से यही सवाल हुआ तो उन्हें जवाब देने में थोड़ी देरी हुई। जिस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कोई टिप्पणी कर दी। तो अनुगम यादव ने सख्त एतराज जताते हुए कहा कि अगर हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। हमने भी इस सेवा में 25 साल गुजारे हैं। अनुगम यादव के इस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त को जवाब दिए जाने के बाद कुछ देर के लिए बैठक में सन्नाटा छा गया। फिर दूसरे विषयों को लेकर बात शुरू की गई और किसी तरह बैठक को निपटया गया। इस प्रसंग के बाद अनुगम यादव को पर्यवेक्षक के पद से हटा दिया गया है। हालांकि आयोग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें हटाने की वजह बैठक में हुई बहस नहीं थी। लेकिन यह भी कहा गया कि अगर कई बार के दौरान के बावजूद पर्यवेक्षक को यह नहीं पता कि उसके क्षेत्र में कितने बूथ हैं, तो यह सही बात नहीं है। इन दोनों प्रसंगों में एक चीज सामान्य है कि ज्ञानेश कुमार पर नाराज होने का आरोप लगा है। भले वे इसके लिए सामने वाले पक्ष को जवाबदेह मानें, लेकिन इससे उनकी नाराजगी या भड़कना या आपा खोना जायज नहीं हो जाता। लोकतंत्र में यकीन और चुनाव को एक पर्व की तरह देखने वालों के लिए यह बड़ी दुखद स्थिति है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था के सामने विधायनीता का संकेत उसकी अपनी कारगुजारियों के कारण खड़ा हो चुका है।



डॉ0 ओ0पी0 मिश्र

66
वैसे भ्रष्टाचार के मामले में निर्णय या अनुशंसा जल्द से जल्द आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और भ्रष्टाचार में भी हित, लाभ, हानि देखा गया ना की मेरिट। कितनी अजीब बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कार्-रवाई के लिए कार्यपालिका को सूचित किया और तब मामला विधायिका तक पहुंचा लेकिन विधायिका ने भी कोई तत्परता ना ही दिखाई।

जहां तक महिला आरक्षण...

आखिर राज्यसभा और विधानपरिषदों में महिलाओं को क्यों नहीं मिलेगा आरक्षण? पूछ रही है आधी आबादी!

भारतीय संसद द्वारा देश की आधी आबादी समझी जाने वाली महिलाओं को महज 33 प्रतिशत आरक्षण देने की एक सकारात्मक नीतिगत पहल तो लोकसभा और विधानसभाओं के लिए की गई लेकिन उच्च सदन समझे जाने वाले राज्यसभा और विधान परिषदों के लिए उन्हें उनके स्वाभाविक हक से क्यों वंचित रखा गया, इसके सिवासी मायने तलाशे जाने लगे हैं। पहला, क्या उनकी विद्वता पर हमारे नेताओं को संदेह है? दूसरा, क्या वह धनकुबेरों की जमात में शामिल नहीं हैं इसलिए इन सदनों के लिए उपयोगी नहीं समझी गई? तीसरा, आरक्षण के भीतर दलितों, पिछड़ों और गरीब वर्गों को आरक्षण देने की मांगों को तत्वजो देने में क्या और किसको हर्ज है? चौथा, जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पर 50 प्रतिशत उन्हें आरक्षण क्यों नहीं दिया गया जबकि कई राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज निकायों में उन्हें यह प्राप्त है? पांचवां, क्या त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण की सीमित सफलता से लोकसभा और विधान सभाओं के रणनीतिकार किसी पशोपेश में हैं? आहए इन सबकी पड़ताल करते हैं, ताकि आधी आबादी का भला हो। कहना न होगा कि उच्च सदन राज्यसभा व विधान परिषदों में महिलाओं को 33% आरक्षण न देने का निर्णय भारतीय राजनीति में लैंगिक समानता और प्रतिनिधित्व पर गंभीर प्रभाव डालता है। यह लोकसभा और विधानसभाओं तक सीमित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, (महिला आरक्षण विधेयक) के कारण है जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाने वाली इन संस्थाओं को बाहर रखता है। इससे निश्चय ही उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, जहां 33% महिला आरक्षण लागू होगा, लेकिन विधान परिषद में इनकी अनुपस्थिति से यह चक्र टूट जाता है। इससे राज्यसभा में महिलाओं का अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व सीमित रहता है, क्योंकि विधान परिषदों वाली विधानसभाओं में कुल आरक्षण प्रभावित होता है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों को आश्चंका है कि यह असंतुलन उच्च सदनों में पुनःप्रधानता को बनाए रख सकता है, जहां नीति-निर्माण पर महिलाओं का प्रभाव



कम रहेगा। इस तकनीकी त्रुटि के सामाजिक और कानूनी निहितार्थ भी हैं। अमर्तो पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी स्थानीय स्तर पर यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, यथा- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों और शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पंचायतों/नगर परिषदों, नगरपालिकाओं और नगर निगमों में 33% तक सीमित रहने से राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व विकास रुक सकता है क्योंकि ओबीसी /एससी/एसटी/गरीब वर्ग महिलाओं के लिए भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की कमी सामाजिक न्याय को प्रभावित करती है। जनगणना और परिसीमन सम्बन्धी प्रावधानों को बदलने के बाद आम चुनाव 2029 से इसे लागू करने के लिए संसद के मौजूदा सत्र में संशोधन विधेयक लाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती का विषय बन चुका है। जहां तक दीर्घकालिक चुनौतियों की बात है तो राज्यसभा और विधान परिषदों में महिलाओं का यह बहिष्कार राजनीतिक दलों को राज्यसभा में महिलाओं को टिकट न देने का अवसर देता है जिससे पितृसत्तात्मक संरचना मजबूत होती है। लिहाजा, इसमें अविलंब सुधार के लिए संविधान संशोधन जरूरी है लेकिन राजनीतिक सहमति की कमी इस दिशा की सबसे बड़ी बाधा है। परिणामस्वरूप, महिलाओं का नीति-निर्माण में योगदान अपूर्ण रहता है, जो समग्र लोकतंत्र को कमजोर करता है। सवाल है कि वो कौन से राजनेता और राजनीतिक दल हैं, जो राज्यसभा और विधान परिषदों में महिलाओं को उनका वाजिब हक भी नहीं देना चाहते। क्या उनकी र्मा, बहनों, बेटियों का स्वाभाविक हक उनके इस कदम से

नहीं मारा जाएगा, उन्हें अपने दिन से ही पूछना चाहिए। सवाल है कि राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं का वर्तमान प्रतिनिधित्व कितना है? तो आंकड़े बताते हैं कि राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वर्तमान में लगभग 13% है, जबकि विधान परिषदों में यह और भी कम, मात्र 5% के आसपास है। अप्रैल 2026 तक राज्यसभा के कुल 245 सदस्यों में से 233 चुने हुए और 12 नामित में महिलाओं की संख्या करीब 30-35 है। वहीं, 6 राज्यों में विधान परिषद के कुल 600 सदस्यों में महिलाओं की संख्या लगभग 30 है। राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिशत 13% के आसपास स्थिर है, जो वैश्विक औसत से कम है। जहां तक विधान परिषद में स्थिति की बात है तो भारत के 6 राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र) में ही विधान परिषद हैं, जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व औसतन 5% है जबकि यह राज्य विधानसभाओं के 9% से भी कम है, जो लैंगिक असंतुलन को दर्शाता है। कुल मिलाकर विधान परिषदों के लगभग 600 सदस्य हैं जो अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश की 100, महाराष्ट्र की 78, बिहार की 75, कर्नाटक की 75, आंध्र प्रदेश की 58 और तेलंगाना की 40 सीटें शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि भारत के कई राज्यों में पहले विधान परिषद अस्तित्व में थी लेकिन बाद में विभिन्न कारणों से समाप्त कर दी गई। जहां तमिलनाडु में 1986 में प्रस्ताव पारित करके समाप्त की गई, वहीं जम्मू कश्मीर में 2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के चलते समाप्त हुई जो अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। वहीं, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश में पहले विधान परिषद थी, जो बाद में समाप्त की गई। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत कोई भी राज्य विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, और फिर संसद में साधारण बहुमत से उसे अनुमोदित करवाकर विधान परिषद का अस्तित्व समाप्त कर सकती है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। यह प्रक्रिया राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करती है। अब सवाल दर सवाल जवाब तलाशते हैं। पहला, क्या उनकी विद्वता पर हमारे नेताओं को संदेह है?

जरा हटके



पश्चिम एशिया की ओर रवाना भी हुए हैं। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ कर रहे हैं, जो विदेश मंत्री अब्बास अराघनी के साथ आधी रात के बाद इस्लामाबाद पहुंचे। वहीं, अमेरिकी टीम का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जिनके साथ विशेष दूत स्टीव हित्कोफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेड कुशनर भी शामिल हैं। इसके साथ अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के अधिकारी ब्रैंड कूपर भी वहां पहुंचे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इन वार्ताओं को 'मेक ऑर ब्रेक' (बनेगा या टूटेगा) करार दिया है। शांति वार्ता से पहले ईरान के

संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ के नेतृत्व में एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचा। वहीं, अमेरिका के साथ होने वाली शांति वार्ता से पहले गालिबाफ ने साफ कर दिया है कि ईरान की पहले की शर्तें पूरी होने पर ही बातचीत आगे बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार, लेकिन हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। गालिबाफ ने यह भी कहा कि तेहरान की मांगों में लेबनान में युद्धविराम शामिल है। ईरान और मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान ने भी कहा कि यह अमेरिका के साथ युद्धविराम का हिस्सा होना चाहिए या हालांकि, अमेरिका और इस्राइल ने इस बात से इनकार किया है। कहा जा सकता है कि ईरान की पूर्व-शर्तों पर अमेरिकी मुहर लगने से ही शांति वार्ता के सफल होने की उम्मीद है। वार्ता के बीच इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतन्याहू ने कहा कि भले ही इस्राइल युद्धविराम का स्वागत करता है, लेकिन लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि वे हिजबुल्ला को खत्म करने के अपने मिशन को जारी रखेंगे। गौरतलब है कि लेबनान पर इस्राइली सेना की ओर से हमलों में कमी नहीं आई है। इस बीच ईरान ने जो प्रमुख शर्तें रखी हैं उससे भी इस शांति वार्ता पर पलीता लगता दिख रहा है। उसकी शर्तों में अमेरिका द्वारा ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को स्थायी रूप से हटाना। होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का नियंत्रण जारी रखना। ईरान को मिले यूरेनियम संवर्धन जारी रखने का अधिकार। क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य बलों की

पूरी तरह वापसी। अमेरिका द्वारा ईरान पर भविष्य में कोई सैन्य हमला न करने का लिखित आश्वासन। संघर्ष के कारण ईरान को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा। ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सभी प्रस्तावों को रद्द करना। लेबनान, इराक और यमन सहित सभी मोर्चों पर युद्ध की पूर्ण समाप्ति। यह सभी शर्तें मान पाना अमेरिका के लिए लगभग असंभव है जबकि अमेरिका ने भी कई अहम शर्तों का पुलिदा थमा दिया है जिसके तहत 3० दिनों का युद्धविराम। ईरान की परमाणु सुविधाओं को नष्ट करना। भविष्य में परमाणु हथियार विकसित नहीं करने का भरोसा। संवर्धित यूरेनियम के भंडार को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) को सौंपना। ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे की आईईएईए द्वारा पूर्ण निगरानी और देश के भीतर यूरेनियम संवर्धन पर पूर्ण। क्षेत्रीय प्रॉक्सी (हिजबुल्ला, हमस आदि) के लिए ईरान का समर्थन खत्म करना। क्षेत्रीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर ईरान के हमलों को रोकना। होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना। ईरान पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को हटाना। ईरान की मिसाइलों की संख्या और उनकी रेंज सीमित करने की मांग। इसलिए दोनों ओर की जुबानी जंग इस शांति वार्ता को एक मसूबे तक पहुंचायेगी, यह कहना बहुत मुश्किल है। काश ऐसा न हो और दुनिया शांति की ओर बढ़े लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है।

अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के बीच इजरायल का हिज़्बुल्लाह पर आक्रामक रुख

पश्चिम एशिया एक बार फिर विरोधाभासों के दौर से गुजर रहा है। एक ओर अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की संभावनाएं बन रही हैं, वहीं दूसरी ओर इजरायल ने लेबनान में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। यह स्थिति न केवल क्षेत्रीय संतुलन को चुनौती दे रही है, बल्कि शांति प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लगा रही है। इजरायल का तर्क साफ है—वह अपनी सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। हिज्बुल्लाह को वह अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, जो ईरान के समर्थन से उत्तरी सीमा पर लगातार दबाव बनाए हुए है। ऐसे में जब अमेरिका और ईरान बातचीत की मेज पर हैं, इजरायल इसे एक अवसर के रूप में देख रहा है कि वह सैन्य कार्रवाई के जरिए अपने दुश्मनों को कमजोर कर दे लेकिन सवाल यह है कि क्या यह रणनीति दीर्घकालिक शांति की राह आसान करती है, या फिर इसे और जटिल बना देती है? शांति वार्ता का मूल उद्देश्य तनाव कम करना होता है, जबकि इजरायल के हमले उसी समय तनाव को बढ़ा रहे हैं। इससे यह संदेश जाता है कि क्षेत्रीय शक्तियां अपने-अपने हितों को प्राथमिकता दे रही हैं, भले ही इससे व्यापक शांति प्रक्रिया प्रभावित हो। लेबनान की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। पहले से ही आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा यह देश अब एक नए संघर्ष की आग में झुलस रहा है। आम नागरिकों के लिए यह हालात और भी भयावह होते जा रहे हैं, जहां हर विस्फोट के साथ जीवन और भविष्य दोनों अनिश्चित होते जा रहे



हैं। इस पूरे घटनाक्रम में ईरान की भूमिका भी अहम है। हिज्बुल्लाह को उसका समर्थन इजरायल के लिए सीधी चुनौती है। ऐसे में अमेरिका-ईरान वार्ता का परिणाम चाहे जो भी हो, इजरायल अपनी सुरक्षा रणनीति में कोई ढील देने के मूढ़ में नहीं दिखता। यह स्थिति एक बड़े सवाल को जन्म देती है—क्या पश्चिम एशिया में शांति केवल कूटनीतिक वार्ताओं से संभव है, या इसके लिए सभी पक्षों को एक समान प्रतिबद्धता दिखानी होगी? जब तक एक ओर बातचीत और दूसरी ओर बमबारी का सिलसिला चलता रहेगा, तब तक शांति एक दूर का सपना ही बनी रहेगी। आज जरूरत इस बात की है कि सभी संबंधित पक्ष संयम बरतें और शांति प्रक्रिया को कमजोर करने वाले कदमों से बचें। वरना, यह विरोधाभास न केवल वर्तमान संकट को गहरा करेगा, बल्कि भविष्य में किसी स्थायी समाधान की संभावनाओं को भी धूमिल कर देगा। पाकिस्तान में चल रही अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के बीच इजरायल हिज्बुल्लाह लेबनान पर जबरदस्त हमले कर रहा है।

सौरभ वाण्योय

दरअसल जब...

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: द्रविड़ सियासत का 'लिटमस टेस्ट' या नए युग का आगाज

तमिलनाडु की राजनीति को समझने के लिए अक्सर वहां की रैलियों का शोर और सिनेमाई सितारों का 'कट-आउट' काफी माना जाता रहा है लेकिन 23 अप्रैल 2026 को विधानसभा की 234 सीटों पर होने वाले चुनाव से ठीक पहले राज्य की गलियों में पसरा 'सन्नाटा' किसी खामोशी का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सियासी मंथन का संकेत है। इस बार का चुनाव केवल सत्ता का हस्तान्तरण नहीं है बल्कि यह इस बात का लिटमस टेस्ट है कि क्या 50 साल पुराना द्रविड़ वर्चस्व अब बहु-ध्रुवीय राजनीति के सामने झुकने को तैयार है? यानी एक ओर क्या राजनीतिक परिपक्वता और त्रिस्तरीय मुकाबले का संकेत है। विशेषकर महिला मतदाता, जो राज्य की आबादी का 51 प्रतिशत है, उन्होंने अपनी चुप्पी से डीएमके और एआईएडीएमके दोनों खेमों की नींद उड़ा दी है हालांकि सभी राजनीतिक दल अपनी नई चुनावी रणनीति के साथ चुनावी जंग में हैं। तमिलनाडु राजनीति के इतिहास पर नजर डाली जाए, तो चुनाव में तमिलनाडु की राजनीति में इस समय द्रविड़ दलों यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कडगम (डीएमके) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कडगम (एडीएमके) को अक्सर एक राजनीतिक महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। ये दोनों प्रमुख दल ही पिछले दशकों से राज्य पर शासन करते आ रहे हैं लेकिन तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार सियासी तस्वीर काफी बदली हुई नजर आ रही है। जहां पहले चुनावों में किसी एक पार्टी या गठबंधन की लहर नजर आती थी, वहीं इस बार ऐसा कोई सियासी परिदृश्य नहीं है। रागम और इंडिया गठबंधन दोनों अपनी-अपनी रणनीति के साथ मैदान में हैं लेकिन जनता का मूढ़ अभी भी शंत और सोच-समझकर फैसला लेने वाला दिख रहा है। राज्य में चुनावी सरगमियों के बीच इस बार चुनावी रैलियों में वह पारंपरिक उन्माद नहीं दिख रहा, जो कभी एमजीआर, जयललिता या करुणानिधि के दौर में होता था। इस बार मतदाता मौन है और लगता है कि जनता इस बार उम्मीदवारों के



चेहरों को नहीं, बल्कि उनके ट्रैक रिकॉर्ड को तोल रही है। यह सन्नाटा बताता है कि मतदाता इस बार 'लहर' के बहाव में नहीं, बल्कि 'परिणाम' के प्रभाव पर वोट करेंगे। मसलन इस बार का चुनाव यह तय करेगा कि क्या तमिलनाडु अपनी पारंपरिक द्रविड़ सीमाओं में ही रहेगा या फिर वह राष्ट्रीय मुख्यधारा की राजनीति और नए क्षेत्रीय चेहरों के लिए अपने दरवाजे खोलेगा। दरअसल जब तमिलनाडु का मतदाता शांत होता है, तो वह अक्सर किसी बड़े 'उलटफेर' की पटकथा लिख रहा होता है। 4 मई के नतीजे केवल एक मुख्यमंत्री नहीं चुनेंगे, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति की अगली आधी सदी का रुख तय करेंगे। सत्तारथी डीएमके अपने 'द्रविड़ मॉडल' और महिला केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं के भरोसे मैदान में है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के लिए यह चुनाव अपनी विरासत को स्थायी बनाने का लड़ाई है। इसमें उनका मजबूत कैडर और सरकारी योजनाओं की जमीनी पहुंच मानी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का चेहरा सबसे बड़ा है, लेकिन गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर कांफेंस, छोटे दलों और वामपंथी दलों में दबी हुई नाराजगी के साथ ही कार्यकर्ताओं के बीच जमीनी स्तर पर तालमेल की कमी एक 'अदृश्य हरा' पैदा कर रही है। वहीं सनातन धर्म जैसे विवादित बयानों ने किस तरह राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन को असहज किया है, उसका असर स्थानीय स्तर पर भाजपा भुनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा के लिए तमिलनाडु हमेशा से एक 'इम्पेचर दुर्ग' रहा है लेकिन इस बार पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है।

राज्यसभा में महिलाओं...

राजेश श्रीवास्तव

कहीं जुबानी जंग बिगाड़ तो नहीं देगी शांति वार्ता का मकसद

पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता चल रही है। एक राउंड वार्ता आमने-सामने हो भी चुकी है और वार्ता को एक दिन के लिए बढ़ाया भी गया है। ऐसे में कुछ तो उम्मीद नजर आ रही है क्योंकि युद्ध विराम अमेरिका और इजरायल दोनों देशों की जरूरत है और दुनिया भी इसी की ओर ताक रही है लेकिन अगर आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के अराघनी के बयानों पर नजर डालें तो युद्ध विराम या फिर शांति वार्ता के सफल होने को उम्मीद बेहद क्षीण होती नजर आती है। ऐसा लगता नहीं है कि कूटनीति की मेज पर होने वाली बातचीत से कोई हल निकलेगा जबकि संभावना जताई जा रही है कि इस अमेरिका-ईरान के बीच इस शांति वार्ता से पश्चिम

एशिया संकट का हल निकल सकता है। लेकिन इसकी उम्मीदें कम ही हैं। ऐसा कहने की सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान। वहीं, ईरान भी अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। पश्चिम एशिया में शांति प्रक्रिया के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद में शांति वार्ता विफल होती है, तो अमेरिका ईरान पर अपने सबसे बेहतरीन हथियारों का इस्तेमाल करके एक बड़ा सैन्य हमला करने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में हालिया तनावियों के बाद अमेरिकी सैनिकों की संख्या 5०००० के पार पहुंच गई है। वहां पहले से ही करीब 25०० मरीन और 25०० नौसैनिक मौजूद हैं। अमेरिकी युद्धपोतों की संख्या भी खाड़ी क्षेत्र में बढ़ी है। वहीं, कई युद्धपोत

डिफेंडिंग चैंपियन को हराया, 60 साल बाद कोई भारतीय मेंस सिंगल्स के फाइनल में पहुंचा

आयुष शेट्टी एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में

इतिहास

रतीय बैडमिंटन के युवा सितारे आयुष शेट्टी ने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। उन्होंने मेंस सिंगल्स क्वार्टर के फाइनल में जगह बनाकर 60 साल का लंबा इंतजार खत्म कर दिया है। आयुष से पहले यह उपलब्धि भारत के दिनेश खन्ना ने 1965 में हासिल की थी, जब उन्होंने न सिर्फ फाइनल खेला बल्कि गोल्ड मेडल भी जीता था। गौरतलब है कि दोनों खिलाड़ी पिछले साल आर्कटिक ओपन में



आयुष ने सेमीफाइनल में टॉप सीड और डिफेंडिंग चैंपियन कुलावत वित्तिदर्सन को तीन गेम में हराया।

आमने-सामने आए थे, जहां वित्तिदर्सन ने सीधे गेम में जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार आयुष ने अपने खेल में सुधार दिखाते हुए न सिर्फ हार का बदला लिया बल्कि फाइनल का टिकट भी हासिल किया। आयुष का सफर इस टूर्नामेंट में बेहद प्रभावशाली रहा है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल

में दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी को 23-21, 21-17 से हराया। इसके अलावा उन्होंने चीनी ताइपे के चिन यू जेन और चीन के ली शी फेंग जैसे मजबूत खिलाड़ियों को भी मात दी। आयुष शेट्टी का यह सफर अचानक नहीं आया, बल्कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है।क्वार्टर फाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया के दिगज और वर्ल्ड नंबर-4 खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी को 23-21, 21-17 से हराया। यह जीत उनके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देने वाली साबित हुई इसके अलावा उन्होंने चीनी ताइपे के चिन यू जेन और चीन के ली शी फेंग जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वियों को भी मात देकर अपनी काबिलियत साबित की। अब सभी की नजरें फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं, जहां आयुष शेट्टी का सामना चाऊ तियेन चेन और शी यूकी के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा।दोनों ही खिलाड़ी विश्व स्तरीय हैं, ऐसे में



दिनेश खन्ना की ऐतिहासिक जीत की याद

भारत के लिए इस चैंपियनशिप में अब तक एकमात्र गोल्ड मेडल दिनेश खन्ना ने 1965 में जीता था। उस समय उन्होंने लखनऊ में खेले गए फाइनल में थाईलैंड के सांगोव रत्तनुसोन को हराकर खिताब अपने नाम किया था।

फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। आयुष शेट्टी का यह प्रदर्शन भारतीय बैडमिंटन के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। युवा उम्र में जिस तरह उन्होंने बड़े-बड़े खिलाड़ियों को हराया है।

आईपीएल में लगातार तीन हार के बाद जीती चेन्नई

दिल्ली को 23 रन से हराया, सैमसन का शतक, ओवर्टन को 4 विकेट

नई दिल्ली, एजेंसी

चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL के मौजूदा सीजन में पहली जीत हासिल कर ली है। लगातार तीन हार के बाद चेन्नई को यह कामयाबी मसीब हुई है। उसने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से हराया। चेंपैक स्टैडियम में DC ने गेंदबाजी चुनी। चेन्नई ने 20 ओवर के बाद 2 विकेट पर 212 रन बनाए। जवाब में दिल्ली 20 ओवर में 10 विकेट पर 189 रन ही बना सकी। जैमी ओवर्टन ने 18 रन देकर 4 विकेट झटके। मैच का स्कोरकार्ड चेन्नई की ओर से संजू सैमसन ने शतकीय पारी खेली।

उन्होंने तीसरी टीम से शतक लगाया है। इससे पहले वे राजस्थान से 2 और दिल्ली से एक शतक लगा चुके हैं। संजू को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।



दिल्ली की पारी में नंबर-6 पर बल्लेबाजी करने उतरे ट्रिस्टन स्टब्स ने 38 बॉल पर 60 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। उनकी पारी में 4 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। चेन्नई की टीम सीजन की पहली जीत से पॉइंट्स टेबल के नंबर-9 पर है। वहीं, दिल्ली लगातार दूसरी हार के बाद

नंबर-4 पर है। चेन्नई के पास 2 और दिल्ली के पास 4 अंक हैं। दिन का पहला मैच जीतने वाली पंजाब की टीम दूसरे स्थान पर है। पंजाब के पास 7 अंक हैं। 213 रन का टारगेट चेज कर रही दिल्ली की टीम 189 रन पर ऑलआउट हो गई। टीम ने आखिरी बॉल पर लुंगी एनगिडी का विकेट गंवाया। इसी के साथ टीम को 23 रन से हार का सामना करना पड़ा। 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर दिल्ली ने 8वां विकेट गंवाया। 189 रन पर ट्रिस्टन स्टब्स 60 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें जैमी ओवर्टन ने नूर अहमद के हाथों कैच कराया। उन्होंने आकिब नबी (4 रन), डेविड मिलर (17 रन) और समीर रिजवी (6 रन) के विकेट लिए।



मल्टी-ऑर्गन फेल्योर के कारण निधन हुआ
आशा भोसले के निधन पर डॉ. प्रतीत समदानी ने बताया, “यह बहुत दुखद है कि आशा भोसले जी का आज निधन हो गया। उन्हें कई मेडिकल समस्याएं थीं और मल्टी-ऑर्गन फेल्योर के कारण उनका निधन हुआ।” आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने बताया, “आज उनका निधन हो गया। जो लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, वे कल सुबह 11 बजे उनके घर आ सकते हैं। अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा।”



साउंड रिकॉर्डिस्ट ने आवाज को खराब बताया था

आशा भोसले ने 50 से 90 के दशक के बीच ओपी नैयर, आरडी बर्मन, खय्याम और बप्पी लहरी जैसे कई संगीतकारों के साथ काम किया। कई सदाबहार गाने गाए। हालांकि, एक समय ऐसा भी था जब इसी आवाज को खराब बताकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो से वापस भेज दिया गया था। आरजे अनमोल के साथ बातचीत में आशा भोसले ने बताया था कि खराब आवाज बताकर उन्हें और किशोर कुमार को रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर जाने के लिए कहा गया था। उन्होंने बताया था कि 1947 में वह किशोर कुमार के साथ जे.बी. रूंगटा के फेमस स्टूडियो में राज कपूर और नरगिस स्टार फिल्म जान पहचान के लिए गाना रिकॉर्ड करने गई थीं। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश थे। आशा भोसले ने पहला गीत मराठी फिल्म 'माझा बाल' (1943) में 'चला चला नाव वाला' गाया था।

मराठी फिल्म में गाया था पहला गाना

8 सितंबर 1933 को आशा भोसले का जन्म एक संघर्ष से जुड़े परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक एक्टर और क्लासिकल सिंगर थे। आशा भोसले स्वतः कोकिला लता मंगेशकर की छोटी बहन थीं। आशा भोसले जब नौ साल की थीं, तभी उनके पिता का निधन हो गया था। इसके बाद उनकी फैमिली पुणे से कोल्हापुर और बाद में मुंबई आ गई। बड़ी बहन लता मंगेशकर के पढ़ाई पर चलेते हुए वह भी संगीत की दुनिया में आईं। आशा भोसले ने पहला गीत मराठी फिल्म 'माझा बाल' (1943) में 'चला चला नाव वाला' गाया था। जबकि बॉलीवुड में उनका पहला गाना 'चुरिया' (1948) फिल्म में 'सावन आया' था।

16 साल की उम्र में भागकर शादी की थी

16 साल की उम्र में आशा भोसले ने बड़ी बहन लता के 31 साल के सेक्रेटरी गणपतराव भोसले से भागकर शादी की थी। लता जी और उनका परिवार इस शादी के सख्त खिलाफ था। इसके कारण उन्होंने आशा से लंबे समय तक बातचीत बंद कर दी थी। शादी के बाद आशा भोसले को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वह घरेलू हिंसा का शिकार हो गई थीं। वह ज़िंदगी से इतनी निराश हो गई थीं कि खुद को खत्म करना चाहती थीं। 1960 में वह पहले पति से अलग हो गईं।

आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाना शुरू किया। इसके बाद साउंड रिकॉर्डिस्ट रॉबिन बटर्जी ने बंगाली में कहा था कि आप लोगों की आवाज माइक में अच्छी नहीं लग रही है। किशोर कुमार समझ गए क्योंकि वह बंगाली जानते थे। उन्होंने आशा भोसले से कहा कि कुछ गड़बड़ है।

देवेंद्र फडणवीस बोले- यह हम सभी के लिए बड़ी क्षति

देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'यह पूरे भारत और दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के लिए दुख का क्षण है। वह सबसे बहुमुखी कलाकारों में से एक थीं। संगीत के प्रति उनकी सेवा और मंगेशकर परिवार का योगदान अतुलनीय रहा है। हमने पहले लता दीदी को खोया और आज यह क्षति देख रहे हैं। हम सभी बहुत दुखी हैं। यह हम सभी के लिए एक बड़ी क्षति है। हम शोक संतप्त परिवार के साथ थीं।' कल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लोअर पॉल स्थित उनके निवास पर लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे शिवाजी पार्क रमशान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्हें पूरा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी।"



आशा भोसले और किशोर कुमार ने एक साथ 600 से अधिक युगल गीत (duet) गाए हैं।

12,000 से ज्यादा गाने गाए

आशा भोसले ने अपने करियर में 14 से अधिक भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए। उनके गाने 'दम मारो दम', 'पिया तू अब तो आजा' और 'चुरा लिया है तुमने' आज भी सदाबहार हैं। आशा भोसले मशहूर थिएटर एक्टर और क्लासिकल सिंगर दीनानाथ मंगेशकर की बेटी और लता मंगेशकर की छोटी बहन थीं। जब वो सिर्फ 9 साल की थीं।

दक्षिण कोरिया में आग से जले दो फायरफाइटर्स की मौत, हंगरी में आम चुनाव के लिए हुआ मतदान

मातम और मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव

विदाई

लेबनान में शोक और गुस्से का माहौल उस समय और गहवा गया, जब इस्राइली हवाई हमले में मारे गए 13 लेबनानी सुरक्षा अधिकारियों को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान महिलाएं काले कपड़ों में चीख-पुकार कर रही थीं और छोटे बच्चे अपने पिता और रिश्तेदारों को पुकारते हुए बिलख रहे थे। अंतिम संस्कार के दौरान हर ओर दुख और पीड़ा का दृश्य था। वर्दीधारी सुरक्षार्थी भी अपने साथियों को याद कर फूट-फूटकर रो पड़े। पिछले एक सप्ताह में लेबनान के विभिन्न हिस्सों में ऐसे सैकड़ों अंतिम संस्कार हो चुके हैं, क्योंकि इस्राइल ने ईरान समर्थित हिजबुल्ला के ठिकानों और लड़ाकों के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। इस्राइल-हिजबुल्ला संघर्ष में अब



तक लेबनान में 2,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। शुकुवार को दक्षिणी शहर नबातियेह में सुरक्षा बलों के मुख्यालय पर हुए इस्राइली हवाई हमले में कई सुरक्षा अधिकारियों की मौत हुई है। यह हमला ऐसे समय हुआ, जब इससे महज दो दिन पहले बेरुत समेत अन्य इलाकों में हुए इस्राइली हमलों में 350 से अधिक लोगों की जान गई थी, जो लेबनान के इतिहास के सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है। इराक की संसद ने शनिवार को कुर्द नेता निजार अमीदी को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया। यह चुनाव संसदीय चुनाव के पांच महीने बाद हुआ, जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। अमीदी की नियुक्ति तब हुई है। जब इराक अमेरिका इस्राइल और ईरान के बीच युद्ध के प्रभाव से जूझ रहा है। अमीदी देश की प्रमुख कुर्द पार्टी पैट्रियॉटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान से जुड़े हैं।

इस्राइल-लेबनान बातचीत टली

लेबनान और इस्राइल, जिनके बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध नहीं हैं, दशकों में पहली बार अगले सप्ताह अमेरिका में प्रत्यक्ष वार्ता शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि अब यह बातचीत टल गई है। दरअसल इस बातचीत के खिलाफ लेबनान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए। जिससे प्रधानमंत्री नवाफ सलाम पर दबाव बढ़ा है। अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लेबनान की सरकार के प्रतिनिधि अब इस्राइल के साथ बातचीत के लिए अमेरिका नहीं जाएंगे। हालांकि अभी दोनों देशों की मुलाकात राजदूत स्तर की होगी।

भारत आएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह, पीएम मोदी का न्योता किया स्वीकार

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेन शाह भारत की यात्रा पर आएंगे। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पीएम बालेन शाह ने इस निमंत्रण को खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया है। यह दौरा दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों को और भी मजबूती देने के इरादे से देखा जा रहा है। पूर्व रैंपर और स्टूडनरल इंजीनियर 35 वर्षीय बालेन काठमांडो के मेयर के रूप में अपनी धाक जमाने के बाद हालिया चुनावों में शानदार जीत हासिल की। उनकी यह पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी। जो उनके राजनीतिक जीवन के लिए एक बड़ा मोल का पत्थर मानी जा रही है।

पाकिस्तान बोला- अमेरिका-ईरान शांति वार्ता में मध्यस्थता जारी रहेगी; युद्धविराम मानने का किया आग्रह

पाकिस्तान ने रविवार को कहा कि वह अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता को सुगम बनाना जारी रखेगा। इसके साथ ही दोनों पक्षों से युद्धविराम का पालन करने का आग्रह किया। अमेरिका और ईरान के बीच लंबी बातचीत बिना किसी सफलता के समाप्त होने के बाद मीडिया को दिए एक संक्षिप्त बयान में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने पिछले 24 घंटों में कई दौर की गहन और रचनात्मक चर्चाओं में मध्यस्थता करने में मदद की है। उन्होंने कहा, 'मैंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मिलकर दोनों पक्षों के बीच गहन और रचनात्मक वार्ता के कई दौरों में मध्यस्थता करने में मदद की, जो पिछले 24 घंटों तक जारी रही और आज सुबह समाप्त हुई।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएई के डिप्टी पीएम से की मुलाकात

अबू धाबी, एजेंसी

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने क्षेत्र की बदलती स्थिति और उसके प्रभावों पर गहराई से बातचीत की। विदेश मंत्री जयशंकर 9 से 12 अप्रैल तक मॉरीशस और यूएई की चार दिनों की यात्रा पर थे। यह उनके इस दो देशों के दौर का अंतिम हिस्सा था। शनिवार शाम को हुई इस मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की। उन्होंने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय क्षेत्र में विकसित हो रहे हालात और उनके परिणाम रहे। बैठक के दौरान जयशंकर ने यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां के नेतृत्व के प्रयासों की जमकर



तारीफ की। उन्होंने भारत की ओर से इसके लिए सराहना व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और यूएई के बीच की व्यापक रणनीतिक साझेदारी आने वाले समय में और भी आगे बढ़ेगी। जयशंकर शनिवार को मॉरीशस की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद यूएई पहुंचे थे। मॉरीशस में उन्होंने 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया था। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य मित्र देशों के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करना था।

